International Year of Cooperatives (IYC) 2025

Format for Monthly Activities Report from Madhya Pradesh for the month -February 2025

Criteria	Details
Sector	PACS/DCCB/StCB/Dairy/Fisheries etc.
Location	State/District/Village level
Event/Activity Name	Special Campaign for Cleanliness in Office and Workplaces Participation in the Global Investors Summit, 2025 held on 24th-25th February, 2025
Brief Information on the Activity	1) In the month of February, records of all district offices, DCCBs and Societies ware updated and organized throughout all districts of the State. A thorough campaign was carried out to clean up office premises, flagged off by the Honbl. Minister of Cooperation himself. 2) The Department participated in **the Global Investors Summit 2025**, a historic event, as it was the first time Cooperative Department of any state had participated in such an event and sought investments from the corporate sector.
Objective	Sending a positive message to the Cooperative sector of the State as part of GoI'sSwachch Bharat campaign. Promotion of Cooperatives as a sector worthy of investments from the corporate sector.

No. of Participants	Per district, an average of 50 participants An estimated 2650 participants in total.
Achievements & Outcomes	1. *At state-level:* enthusiastic coverage of the campaign by the media in presence of the Honbl. Minister of Cooperation, Registrar and Commissioner, Cooperative and all senior level officials of the Department. *At district-level:* Awareness and interest generation among the general public regarding IYC due to the activities carried out by the administration. 2. Introduction of the CPPP model – Cooperative Public Private Partnership 3. MoUs worth Rs 2305 crore signed between various investor companies and cooperative societies (PACS)
Photographs & A V Content	Representative photo/video attached.
Additional Remarks	All 4500 M-PACS, 38 DCCBs, 53 District officers and 5000 other societies of the State attracted the public's attention towards the importance of maintaining hygiene, sanitation and general cleanliness in their respective workplaces.

Joint Commissioner
Office o/ Registrar, Cooperative Societies
and Commissioner, Cooperative, Madhya Pradesh
Bhopal, Madhya Pradesh

अपेक्स बैंक
APEX BANK

अपेक्स बैंक
APEX BANK

का नाम सेवा सह. समिति मर्या. कर्री (वमनी)
दो गज दूरी

EXP
EXP
RACK 2 CHCDS
RACK 3 PACS COMPUTERISATION

बिन सहकार
नही उद्धार
सीहोर जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
'' स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता ''
अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता दिवस
दिनांक 13 फरवरी 2025
कार्यालय उप पंजीयक सहकारी
संस्थाऐ जिला सीहोर म.प्र.
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
'' स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता ''
अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता दिवस
दिनांक 13 फरवरी 2025

INVEST
MOU
MOU

Welcome to the Land of Possibilities
GATE 3
POLICE
RENEW
REBUILD

INVEST
MADHYA PRADESH
MOU
INVEST

Strength of Cooperative Public Private Partnership
Cooperative Sector
Public Sector
Private Sector
INVEST

MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LTD

SESSION
HALL-3
सहकार का नवाचार
भागीदारी से उद्धार

पत्रिका

जीआइएस में मुख्यमंत्री ने कहा-निवेशकों को सरकार पूरा सहयोग करेगी

सहकारिता में हुए 2305 करोड़ के एमओयू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. सहकारिता विभाग के थीमेटिक सेशन में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के तहत 2305 करोड़ के एमओयू किए गए। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश विंग डे-टू-डे काम करेगी। वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने इन्वेस्टर से जुड़ने का आग्रह किया कि सभी देश-प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ में योगदान दें। मप्र का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलेगा।

विभाग में इतने के एमओयू

रिलायंस	1,000 करोड़
मैजेस्टिक बासमती रायसेन	1,000 करोड़
आरएम ग्रुप	100 करोड़
मशरूम वर्ल्ड भोपाल	100 करोड़
वी विन लिमिटेड भोपाल	40 करोड़
न्यूट्रेलिस सहकारी समिति नोएडा	30 करोड़
एग्रीविस्टा एआइ	25 करोड़
सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा	10 करोड़

देश में एक लाख पैक्स का होगा कंप्यूटरीकरण: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि एक लाख पैक्स देश में हैं। 30 करोड़ की आबादी जुड़ी है। सहकारिता में पैक्स को कम्प्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं विश्वास करें अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के पए कीर्तिमान रचेगी। मप्र का नया सीपीपीपी मॉडल को भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग कर आगे बढ़ाया जायेगा। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा, जीआइएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश में एक करोड़ 9 लाख सदस्य है। 16 हजार आउटलेट। निवेशकों से कहा, मप्र में पैक्स हर जरूरत पूरी करेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन की बात

मप्र अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। 10 वर्ष में इस क्षेत्र में प्रदेश ने 11 गुना वृद्धि की। वर्तमान में कुल स्थापित बिजली क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 24% हो गई है। यह जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने दी। विशेषज्ञों ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में मप्र देश का अग्रणी राज्य होगा।

नए आयाम स्थापित करेंगे

एमएसएमई समिट में सीएम ने कहा कि सरकार जो भी कमिटमेंट कर रही है और जिस पारदर्शिता के साथ नीतियां लागू कर रही है, वह औद्योगिक विकास के लिए अहम हैं। हमारी सरकार और उद्यमी मिलकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे।

26/02/2025 | Bhopal | Page : 17
Source : https://epaper.patrika.com/

सीपीपीपी माडल के तहत सहकारिता क्षेत्र में होगा विकास

2,305 करोड़ के 19 एमओयू

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में अब को-आपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) माडल के तहत सहकारिता क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। जिसकी घोषणा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआइएस) के दौरान की है। जीआइएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र के विशेष सत्र का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की मौजूदगी में रिलायंस सहित अन्य बड़ी कंपनियों के साथ कुल दो हजार 305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू किए गए हैं, जबकि वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। जिस क्षेत्र में भी निवेशक काम करना चाहते हैं, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। सीपीपीपी माडल सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा। मध्यप्रदेश का सीपीपीपी माडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने के ध्येय तक सहकारिता को मूल बनाकर पहुंचा जा सकता है। सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की जाएगी। निवेश विंग हर दिन काम करेगी और वह स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। मध्यप्रदेश में एक करोड़ नौ लाख सदस्य हैं और 16 हजार आउटलेट का नेटवर्क है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने कहा कि देशभर में एक लाख पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) और इनसे 30 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है। सहकारिता में पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन का काम चल रहा है, अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के नए कीर्तिमान रचेगी।

जीआइएस में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहरलाल खट्टर और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच कुछ ऐसी चर्चा हुई कि तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। • मोहम्मद अबरार खान

स्थानीय निकाय आय बढ़ाने पर ध्यान दें: खट्टर

भोपाल : केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत वर्ष-2047 की कल्पना की है। इस लक्ष्य को हासिल करने में शहरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भोपाल, इंदौर मेट्रो लाइन का विस्तार इस तरह से किया जाए कि इसका फायदा समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल सके। बढ़ती शहरी आबादी का आकलन सही रूप में करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी के जरिए पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित कर रही है। कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण और कार्बन क्रेडिट का फायदा देने वाली प्रोत्साहन नीति का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। उन्होंने महापौरों से वर्चुअल चर्चा में कहा कि आदर्श नगर निगम बनाने के लिए स्थानीय निकायों को आय बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। खट्टर मंगलवार को भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग ले रहे थे। उन्होंने 'अनलाकिंग लैंड वैल्यू' पर निवेशकों को संबोधित किया। खट्टर ने कहा नए क्षेत्रों की योजना बनाते समय टीडीआर और टीओडी नीतियों का उपयोग किया जाए। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री विजयवर्गीय ने सत्र में कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों में आय के स्रोत बढ़ाये जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में जारी की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी से शहरों का समग्र रूप से विकास हो सकेगा। आवास से जुड़ी नई नीतियों में डेवलपर्स और बिल्डर्स को कई रियायतें दी गई हैं।

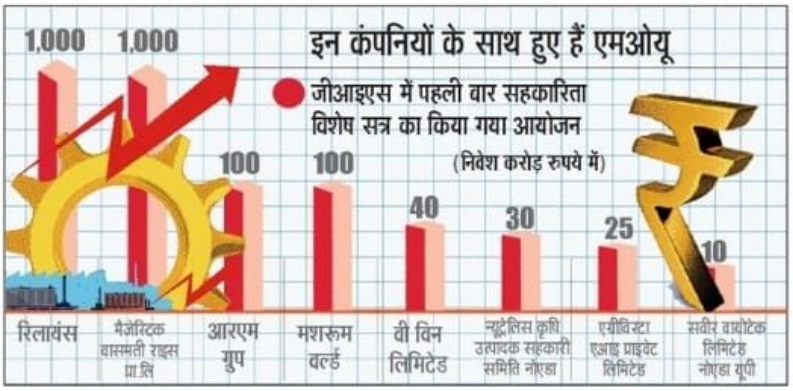

मध्य प्रदेश बनेगा लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग का हब

मप्र लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग का हब बनेगा। इसके लिए प्रदेश में सभी संभावनाएं मौजूद हैं। यह बात लाजिस्टिक्स: कनेक्टिंग एमपी टू द वर्ल्ड सत्र में विशेषज्ञों ने कही। सत्र में औद्योगिक कारिडोर, डिजिटल एकीकरण, निवेश अवसरों और लाजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विचार-विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश में नियमों को सरल बनाने, एमएसएमई को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने से प्रदेश एक लाजिस्टिक पावर हाउस बनाने की ओर बढ़ रहा है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के सचिव जान किंग्सले ने बताया कि मध्य प्रदेश मजबूत परिवहन नेटवर्क, मल्टी-माडल कनेक्टिविटी और लाजिस्टिक्स इकोसिस्टम के व्यापक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के मध्य स्थित होने की वजह से रोड रेल और एयर कनेक्टिविटी आसान हो गई है। एनआइसीडीसी के सीईओ एवं एनएलडीएसएल के चेयरमैन राजत कुमार सैनी ने बताया कि मध्य प्रदेश लाजिस्टिक्स की लागत को प्रभावी बनाने और परिवहन सुविधाओं को डिजिटल माध्यमों से अधिक सशक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। डब्ल्यूएआइपीए के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुष्यंत ठाकोर ने कहा, मप्र का रणनीतिक भौगोलिक स्थान व विकसित लाजिस्टिक्स नेटवर्क इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।

3,300 हेक्टेयर क्षेत्र में उज्जैन में धार्मिक नगर होगा विकसित

भोपाल : मेले का मतलब है मेलजोल बढ़ाना और इसमें पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन में 3,300 हेक्टेयर क्षेत्र में धार्मिक नगर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, साधु, संत, महंत आदि को स्थायी रूप से अपने आश्रम निर्मित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इनमें अन्न क्षेत्र के साथ स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि का संचालन किया जा सकेगा। यह बात मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने पर्यटन व संस्कृति और अनलाकिंग अर्बन लैंड वैल्यू पर केंद्रित सत्रों में कही। डा. यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल की गई है। सरकार पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों पर विशेष समिट करेगी। इंदौर, नागदा, उज्जैन, देवास, मक्सी (शाजापुर), पीथमपुर (धार) के आठ हजार वर्ग किमी क्षेत्र को मिलाकर मेट्रोपालिटन के रूप में विकसित करने की योजना है।

800 करोड़ रुपये का निवेश टेक्सटाइल क्षेत्र में अरविंद ग्रुप करेगा

भोपाल : मप्र में उद्योगों के लिए पानी और बिजली की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धता है। नए उद्योग स्थापित करने के लिए सभी अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम से कम समय में दी जाती हैं। राज्य की सभी विशेषताएं टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर स्थान प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही है। अरविंद ग्रुप टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग में 800 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा। वहीं, भोपाल में ओवीटी कंपनी 100 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। यह जानकारी टेक्सटाइल एवं एपेरल सत्र में दी गई। अरविंद ग्रुप के ग्रुप हेड कार्पोरेट अफेयर्स डा. परम शाह ने बताया कि मेक इन इंडिया मिशन के सपने को साकार करते हुए उनकी कंपनी रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। 800 करोड़ रुपये के निवेश से इकाई की स्थापना की जाएगी। वहीं, ओवीटी कंपनी के सीइओ इंगो सोयेलर ने कहा कि टेक्निकल फेब्रिक के वर्तमान वस्त्र उद्योग में कई उपयोग हैं एवं यह तेजी से बढ़ता उद्योग है।

व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीआईएस के दूसरे दिन थीमेटिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, म.प्र. सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। डॉ. यादव की मौजूदगी में 19 एमओयू होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिये उपयोगी साबित होंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल राशि 2305 करोड़ रूपये की राशि में 19 एमओयू किये गये। श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि एक लाख पैक्स देशभर में हैं और 30 करोड़ की आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई है। इस अमृतकाल में यही वह क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सहकारिता में पैक्स को कम्प्यूटराईजेशन का काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं विश्वास करें अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के नये कीर्तिमान रचेगी। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि जीआईएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। हर क्षेत्र में सहकारिता की समितियां है। उन्होंने बातया कि मध्यप्रदेश में एक करोड़ 9 लाख सदस्य है और 16 हजार आउटलेट का नेटवर्क है। कार्यक्रम में बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के संस्थापक एवं अध्यक्ष राधेश्याम चांडक, रिलायंस के कुमार अभिषेक, प्रतिभा सिन्टेक्स के श्रेयसकर चौधरी, एग्रीविस्टा के राजीव सिंह, वैधनाथ के अनिरूद्ध गौर, भारतीय बीज के जे.पी. सिंह, मेजेस्टिक बासमती के विज्ञान लोधा, आरएम ग्रुप के अनिमेष जैन, मशरूम वर्ल्ड के समीर सागर, वी विन के अभिषेक गुप्ता, न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति के प्रदीप द्विवेदी, सावीर बॉयोटेक के संदीप सुदन आदि ने अपने विचार साझा किये।

सहकारिता क्षेत्र में एमओयू

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू हुए। जिसमें रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपये। मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपये, आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये, मशरूम वर्ल्ड भोपाल द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये। वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा राशि 40 करोड़ रुपये। न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा यूपी द्वारा राशि 30 करोड़ रुपये। एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राशि 25 करोड़ रुपये। सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा यूपी द्वारा राशि 10 करोड़ रुपये। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहकारिता क्षेत्र में 2305 करोड़ से अधिक के एमओयू शामिल हैं।

सहकारिता : एनडीडीबी और सांची दुग्ध संघ के बीच 2305 करोड़ रुपये के करार

भोपाल। सहकारिता के क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि दिखाई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में 2305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू साइन हुए। इसके साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी को-आपरेटिव फेडरेशन के बीच भी प्रदेश में संचालित छह सांची दुग्ध संघों के संचालन को लेकर अनुबंध हुआ। मध्य प्रदेश में सीपीपीपी-कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होगा।

सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की जाएगी। रिलायंस, बैद्यनाथ जैसी बड़ी कंपनियां सहकारिता क्षेत्र में निवेश करेंगी। सांची दुग्ध संघ के एमडी सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एनडीडीबी न तो दुग्ध संघों को अपने आधिपत्य में लेगा और न ही ब्रांड सांची के नाम में बदलाव करेगा। ब्यूरो

सात बिंदुओं पर अनुबंध

अधिकारियों ने बताया कि सांची और एनडीडीबी के बीच प्रमुख सात बिंदुओं पर अनुबंध हुआ है। इसमें सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के साथ इससे जुड़े लोगों को एनडीडीबी प्रशिक्षण दिलाएगा। बोर्ड ही सभी दुग्ध संघों के प्लांट को अपग्रेड करेगा। दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना होगा। दुग्ध संघों के क्षेत्र में उपयुक्त विपणन प्रणाली लागू की जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर दुग्ध संघ का उन्नयन और रीवा-शहडोल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी सांची की ब्रांड बिल्डिंग मजबूत करनी होगी।

रिलायंस और वैद्यनाथ ग्रुप करेंगे सहकारिता में निवेश

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। मुख्यमंत्री जीआईएस के दूसरे दिन थीमेटिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इंवेस्टर काम करना चाहते हैं, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल 2305 करोड़ रुपए की राशि में 19 एमओयू किए। मंत्री सारंग ने कहा कि मप्र का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा।

सीपीपीपी के तहत 2305 करोड़ के 19 एमओयू

- रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपए के एमओयू।
- वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।
- मैजेस्टिक बासमती राइस रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपए।
- आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपए।
- मशरूम वर्ल्ड भोपाल ने 100 करोड़ रुपए का एमओयू किया।
- वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा राशि 40 करोड़ रुपए।
- न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक समिति नोएडा यूपी द्वारा राशि 30 करोड़ रुपए।
- एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राशि 25 करोड़ रुपए।
- सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा द्वारा राशि 10 करोड़ रुपए।

THE FREE PRESS JOURNAL

Cooperative sector: 19 MoUs worth ₹ 2,305-crore signed

Our Staff Reporter
BHOPAL

As many as 19 Memorandum of Understanding (MoU) worth Rs 2305 crores were signed in the Co-operative sector with an aim to boost farmers' income while offering raw material sourcing avenue for private companies.

The MoUs were inked during the Thematic Session of Co-operative department held on concluding day of Global Investors Summit (GIS) on Tuesday.

Addressing the session, Chief Minister Mohan Yadav assured the investors that the government will provide all the necessary help.

Praising the Cooperative Public-Private Partnership (C-PPP) Model of Cooperative sector, Yadav said that it will change the course of the cooperatives. Cooperative minister Vishvas Sarang announced the establishment of an investment wing in the cooperative department. The minister said that the wing will work on a day-to-day basis and he himself would monitor it.

Additional Chief Secretary Ashok Varnwal stated that it is for the first time that a cooperative department has been brought to the GIS as in every sector there are cooperative committees.

INVESTMENT PROPOSALS RECEIVED, MoUs SIGNED

- Reliance Rs 1,000 crore
- Majestic Basmati Rice Pvt Ltd, Raisen Rs 1,000 crore
- RM Group Rs 100 crore
- Mushroom World Bhopal Rs 100 crore
- We Win Limited, Bhopal Rs 40 crore
- Baidyanath Group - NA

GOI Secretary textile Neelam Sami Rai having one-to-one meeting with CM Mohan Yadav

मुख्यमंत्री ने सहकारिता के थीमेटिक सेशन को किया संबोधित

व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

स्वदेश ज्योति संवाददाता, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीआईएस के दूसरे दिन थीमेटिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, म.प्र. सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में 19 एमओयू होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिये उपयोगी साबित होंगे।

मप्र का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता में नई क्रांति लायेगा: सारंग : सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल राशि 2305 करोड़ रूपये की राशि में 19 एमओयू किये गये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है।

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में एमओयू की जानकारी

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू हुए हैं।

- रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपये
- वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।
- मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपये
- आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये

मशरूम वर्ल्ड भोपाल द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये

- वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा राशि 40 करोड़ रुपये
- न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा यूपी द्वारा राशि 30 करोड़ रुपये
- एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राशि 25 करोड़ रुपये
- सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा यूपी द्वारा राशि 10 करोड़ रुपये

सहकारिता : एनडीडीबी और सांची दुग्ध संघ के बीच 2305 करोड़ रुपये के करार

भोपाल। सहकारिता के क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि दिखाई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में 2305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू साइन हुए। इसके साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी को-आपरेटिव फेडरेशन के बीच भी प्रदेश में संचालित छह सांची दुग्ध संघों के संचालन को लेकर अनुबंध हुआ। मध्य प्रदेश में सीपीपीपी-कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होगा।

सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की जाएगी। रिलायंस, बैद्यनाथ जैसी बड़ी कंपनियां सहकारिता क्षेत्र में निवेश करेंगी। सांची दुग्ध संघ के एमडी सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एनडीडीबी न तो दुग्ध संघों को अपने आधिपत्य में लेगा और न ही ब्रांड सांची के नाम में बदलाव करेगा। ब्यूरो

सात बिंदुओं पर अनुबंध

अधिकारियों ने बताया कि सांची और एनडीडीबी के बीच प्रमुख सात बिंदुओं पर अनुबंध हुआ है। इसमें सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के साथ इससे जुड़े लोगों को एनडीडीबी प्रशिक्षण दिलाएगा। बोर्ड ही सभी दुग्ध संघों के प्लांट को अपग्रेड करेगा। दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना होगा। दुग्ध संघों के क्षेत्र में उपयुक्त विपणन प्रणाली लागू की जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर दुग्ध संघ का उन्नयन और रीवा-शहडोल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी सांची की ब्रांड बिल्डिंग मजबूत करनी होगी।

सीपीपीपी मॉडल के 19 एमओयू किए गए

थीमेटिक सत्र को संबोधित सीएम ने आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, म.प्र. सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। इस मौके पर सीपीपीपी मॉडल पर 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू किए गए। इसमें रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपये,वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपये एवं आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव सौंपे गए। इनके अलावा मशरूम वर्ल्ड सहित दूसरे निवेशकों ने भी अपने प्रस्ताव सौंपे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है।